



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]
No. 29]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

सं. टीएएमपी/10/98-विविध.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार पत्तन संपत्तियों के प्रयोग से संबंधित दरों का मान और शर्तों का विवरण निर्धारित करने के संबंध में सही कानूनी स्थिति का उल्लेख करता है।

मामला सं० टीएएमपी/10/98—विविध

आदेश

(मार्च, 2000 के 15वें दिन को पारित किया गया)

1.1 महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा इस प्राधिकरण को दरों का मान तैयार करने, जिसका भुगतान करने पर और शर्तों का विवरण तैयार करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत किसी पत्तन के बोर्ड से संबंधित अथवा बोर्ड के स्वामित्व अथवा बोर्ड के अधिकार वाली किसी संपत्ति अथवा धारा 49(1) में वहीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पत्तन की सीमा अथवा पत्तन की पहुंच में किसी भी स्थान का प्रयोग किया जाएगा। इस कानूनी स्थिति के बारे में कुछ क्षेत्रों में संदेह व्यक्त किया गया है। इसलिए, इस प्राधिकरण ने सही कानूनी स्थिति को विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हुए अपने दिनांक 4 जनवरी, 99 और 24 अगस्त, 99 के पत्र सं० टीएएमपी/10/98—विविध द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को पत्र लिखे थे।

1.2 मुंबई पत्तन न्यास हमारे संदर्भगत पत्र से संतुष्ट नहीं रहा है। वे पत्तन क्षेत्र और पत्तन की पहुंच से बाहर वाली पत्तन संपत्तियों के पट्टों की दरें और शर्तें निर्धारित करने के प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार पर लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं। इन परिस्थितियों में, इस संबंध में सही कानूनी स्थिति का उल्लेख करते हुए हम यह आदेश जारी कर रहे हैं।

2.1 प्रसंगाधीन मुद्दे से संबंधित मूल विधान में दो प्रावधानों से संबंधित धारा 29 और धारा 49 हैं। जबकि, धारा 29 में वहीं इस प्राधिकरण को बोर्ड में निहित सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के लिए दरें निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है, धारा 49 उसमें उल्लिखित सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली संपत्ति की सभी श्रेणियों से संबंधित है।

2.2 धारा 29 (क) के अंतर्गत वहीं सभी संपत्तियां, परिसंपत्तियां और निधियां तथा दरें लागू करने के केन्द्रीय सरकार में निहित सभी अधिकार अथवा जैसा भी मामला हो, "निर्धारित दिवस" से तत्काल पूर्व पत्तन के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य प्राधिकरण, बोर्ड में निहित रहेंगे।

2.3 धारा 49 बोर्ड से संबंधित संपत्ति के प्रयोग के लिए दरों के मान और शर्तों के विवरण से संबंधित है। जब कोई संपत्ति पट्टे पर अथवा किराए पर दे दी जाती है और पट्टाधारक अथवा किराएदार द्वारा प्रयोग की जाती है, तब भी वह संपत्ति बोर्ड के पास रहती है।

धारा 49 की उपधारा 1 द्वारा प्राधिकरण को दरों का मान तैयार करने, जिसका भुगतान करने पर और शर्तों का विवरण तैयार करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत किसी पत्तन के बोर्ड से संबंधित अथवा बोर्ड के स्वामित्व अथवा बोर्ड के अधिकार वाली किसी संपत्ति अथवा इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पत्तन की सीमा अथवा पत्तन की पहुंच में किसी भी स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। इन प्रयोजनों को खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, खंड (घ) में बोर्ड से संबंधित अथवा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी संपत्ति के किसी अन्य प्रयोग का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

2.4 यह उल्लेखनीय है कि विधान में कोई भी संबंधित प्रावधान पत्तन क्षेत्र के भीतर अथवा पत्तन क्षेत्र से बाहर स्थित संपत्तियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। तर्कसंगत बात यह है कि संपत्ति बोर्ड से संबंधित रहेगी अथवा बोर्ड के स्वामित्व में रहेगी अथवा बोर्ड के अधिकार में रहेगी अथवा यह ऐसा कोई स्थान होगा जो पत्तन क्षेत्र अथवा पत्तन पहुंच के भीतर होगा।

2.5 इस मूलांकन से यह स्पष्ट होगा कि विधान इस प्राधिकरण को कहीं भी स्थित और किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए बोर्ड से संबंधित किसी संपत्ति के प्रयोग के लिए दरों का मान और शर्तों का विवरण निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

2.6 यदि विधायिका का यह आशय होता कि यह प्राधिकरण पत्तन क्षेत्र से बाहर स्थित संपत्तियों के लिए दरें/शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता, तब सामान्यतया विधान में ही इस संबंध में प्रावधान होता।

3.1 एमबीपीटी ने जयंतीलाल धरमसी बनाम मुंबई पत्तन न्यासी बोर्ड के मामले में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय 1990 में पारित किया गया था अर्थात् कानून के अनुसार यह 1997 में संशोधन से पूर्व विद्यमान था। यह भी उल्लेखनीय है कि उल्लिखित निर्णय में धारा 34 वहीं के अंतर्गत सरकार के साथ किए जाने वाले पत्र-व्यवहार के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया था।

3.2 तथापि, वर्तमान प्रसंग में दरें और शर्तें निर्धारित करने संबंधी इस प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में वर्ष 1997 में संशोधन के कारण धारा 49 वहीं के प्रयोजनार्थ "बोर्ड" के स्थान पर इस प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया गया है। किसी महापत्तन न्यास का यह आशय नहीं हो सकता कि उसके न्यासी बोर्ड का केवल कुछ संपत्तियों के संबंध में क्षेत्राधिकार है और अन्य पर नहीं, किसी भी न्यास के न्यासी बोर्ड का इसकी सभी संपत्तियों पर निर्विवाद अधिकार है। चूंकि, इस प्रसंग में "बोर्ड" के स्थान पर यह प्राधिकरण स्वयंमेव प्रतिस्थापित हो चुका है, इसलिए बोर्ड के अधिकार प्राप्त करना आवश्यक था और विधान में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए न्यास की संपत्तियों पर अधिकारों (बोर्ड को पहले प्राप्त) को प्राप्त करना आवश्यक था।

3.3 धारा 34 में वहीं बोर्ड की ओर से निष्पन्न की जाने वाली संविदा का उल्लेख किया गया है। इसमें बोर्ड के अपेक्षित पूर्वानुमोदन और केन्द्रीय सरकार के अपेक्षित पूर्वानुमोदन का उल्लेख किया गया है। तथापि, बोर्ड में निहित संपत्तियों/परिसंपत्तियों के लिए दरें/शर्तें निर्धारित करने के वास्ते इस प्राधिकरण को शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति पत्तन क्षेत्र के भीतर संपत्ति तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि यह बोर्ड में निहित सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों से संबंधित है।

संक्षेप में, धारा 34 संविदाओं के क्रियान्वयन के तरीके से संबंधित है और इसमें उन आकस्मिकताओं का उल्लेख है, जिनमें केन्द्रीय सरकार का (पूर्व) अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसमें पत्तन क्षेत्र के भीतर और पत्तन क्षेत्र के बाहर की संपत्तियों में कहीं कोई भेद नहीं किया गया है। धारा 29 (3) वहीं के संदर्भ में, इस प्राधिकरण को बोर्ड में निहित सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के लिए दरें/शर्तें निर्धारित करनी होती है।

4. परिणामतः और उपर्युक्त कारणों को देखते हुए तथा समग्र ध्यान देने के आधार पर प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय करता है:—

- (i) दरों का मान और शर्तों का विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ इस प्राधिकरण को किसी महापत्तन न्यास की कहीं भी स्थित सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- (ii) महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 49 (1) के अंतर्गत यह प्राधिकरण संपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के प्रयोग के लिए दरों का मान और शर्तों का विवरण तैयार करेगा:—
 - (क) बोर्ड से संबंधित संपत्ति।
 - (ख) बोर्ड के स्वामित्व में संपत्ति।

- (ग) बोर्ड के अधिकार में संपत्ति ।
 (घ) पत्तन क्षेत्र या पत्तन की पहुंच के भीतर किसी भी स्थान पर संपत्ति ।
 (iii) दरों का मान और शर्तों का विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी महापत्तन न्यास की सभी संपत्तियों से संबंधित सभी पट्टा मामले (बिना किसी समय-सीमा के) इस प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर आएंगे ।

5. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के तत्काल पश्चात प्रभावी हो जाएगा ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

No. TAMP/10/98-Misc.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby sets out the correct legal position in respect of its power to prescribe Scale of Rates and Statement of Conditions for use of port properties as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/10/98-Misc.

ORDER

(Passed on this 15th day of March 2000)

1.1. This Authority is empowered by the Major Port Trusts Act (1963) to frame the Scale of Rates on payment of which and a Statement of Conditions under which any property belonging to the Board or in possession of the Board or in occupation of the Board or any place within the limit of the Port or Port approaches will be used for the purposes specified in Section 49 (1) *ibid.* A doubt arose in some quarters about this legal position. This Authority had, therefore, addressed all the Major Port Trusts, vide its communications No. TAMP/10/98-Misc. dated 4 January 99 and 24 August 99, explaining in detail the correct legal position.

1.2. The Mumbai Port Trust (MBPT) has not been convinced by our communications in reference. They have persisted in questioning the jurisdiction of this Authority to prescribe rates and conditions of leases of port properties outside the port area and port approaches. In the circumstance, we feel constrained to issue this order setting out the correct legal position in this regard.

2.1. The two provisions in the Statute basic to the issue in contention are Section 29 and Section 49. Whereas Section 29 *ibid* empowers this Authority to fix rates for all properties and assets vested in the Board, Section 49 deals with all categories of property used for the purposes given thereunder.

2.2. Under Section 29(a) *ibid*, all property, assets and funds, and all rights to levy rates vested in the Central Government or, as the case may be, any other Authority for the purposes of the Port immediately before 'the appointed day' shall vest in the Board.

2.3. Section 49 deals with the Scale of Rates and Statement of Conditions for use of property **belonging** to the Board. When a property is leased or let out, it is used by the lessee or hirer; but, the property continues to belong to the Board.

Sub-Section 1 of Section 49 empowers this Authority to frame the Scale of Rates on payment of which and a Statement of Conditions under which any property belonging to or in possession or occupation of the Board, or any place within the port area or the port approaches may be used for the purposes specified thereunder. These purposes are specified in Clauses (a) to (c). Clause (d), however, clearly stipulates any other use of any property belonging to or provided by the Board.

2.4. It is noteworthy that none of the relevant provisions in the Statute makes a distinction between properties situated within the port area or situated outside the port area. All that is relevant is that the property shall belong to the Board; or, it shall be in possession of the Board; or, it shall be in occupation of the Board; or, it shall be any place within the limits of the port area or the port approaches.

2.5. In this reckoning, it will be clear that the Statute empowers this Authority to fix the Scale of Rates and Statement of Conditions for use of any property belonging to the Board, wherever situated, and put to any use.

2.6. Had it been the intention of the Legislature that this Authority cannot fix rates/conditions for properties situated outside the port area, in the normal course, there would have been a provision to that effect in the Statute itself.

3.1. The MBPT has sought to rely on a judgement of the Hon'ble High Court of Bombay in the case Jayantilal Dharamsi Vs Board of Trustees of Port of Mumbai. It has to be recognized in this context that the said judgement was passed in 1990, i.e., with reference to the law as it existed prior to the amendments in 1997. Also, it has to be appreciated, the focus in the ruling cited was about references to be made to the Government under Section 34 *ibid*.

3.2. In the present context, however, the reference is to the jurisdiction of this Authority to prescribe rates and conditions. By virtue of the amendments made in 1997 to the Major Port Trusts Act (1963), this Authority has replaced 'the Board' for the purpose of Section 49 *ibid*. It cannot be the contention of any Major Port Trust that its Board of Trustees has jurisdiction only in respect

of certain properties and not others; the Board of Trustees for any Trust has unquestioned rights over all its properties. Since this Authority has replaced 'the Board' in this context, *ipso facto*, it must be held to step into the shoes of the Board and inherit all the rights (enjoyed earlier by the Board) to the Trust properties for the purposes given in the Statute.

3.3. Section 34 *ibid* deals with the mode of executing a contract on behalf of the Board. It lays down when previous approval of the Board is required and when previous approval of the Central Government is required. For prescribing rates/conditions, however, for properties/assets vesting in the Board, it is this Authority which has been empowered. This power is not restricted to property within the port area; it relates to **all** property and assets vesting in the Board.

In short, Section 34 deals with the mode of execution of contracts and specifies the contingencies in which (previous) approval of the Central Government will be required. It does not anywhere distinguish between properties within the port area and outside the port area. In terms of Section 29(3) *ibid*, this Authority has to prescribe rates/conditions for **all** properties and assets **vesting** in the Board.

4. In the result, and for the reasons given above, based on a collective application of mind, this Authority hereby decides as follows:-

- (i). For purposes of framing Scale of Rates and Statement of Conditions, this Authority has jurisdiction over **all** the properties and assets, wherever located, of a Major Port Trust.
- (ii). Under Section 49 (1) of the Major Port Trusts Act, this Authority will frame the Scale of Rates and the Statement of Conditions for use of the following categories of property:
 - (a). Property belonging to the Board.
 - (b). Property in possession of the Board.
 - (c). Property in occupation of the Board.
 - (d). Property in any place within the limits of the port area or port approaches.
- (iii). For purposes of framing Scale of Rates and Statement of Conditions, all lease cases (irrespective of any time limitation) relating to all the properties of a Major Port Trust shall be seen to fall within the jurisdiction of this Authority.

5. This Order shall come into force with immediate effect after notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman
[Advt./III/IV/Ext./143/99]